क्यों महत्वपूर्ण है औद्योगिक नीति

लेखक- संतोष मेहरोत्रा (प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, जेएनयू)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-III भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

17 मई, 2019

"कोई भी बड़ा देश एक मजबूत विनिर्माण क्षेत्र के बिना गरीबी को कम करने या आर्थिक विकास को बनाए रखने में कामयाब नहीं हो सका है।"

2017 में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का योगदान केवल 16% था और 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद से एक ठहराव की शुरूआत हुई थी। प्रमुख एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ विषमता महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, मलेशिया ने सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण के अपने हिस्से को तीन गुना करते हुए 24% तक बढ़ा लिया, जबकि थाईलैंड का हिस्सा 13% से बढ़कर 33% (1960-2014) हो गया। भारत में विनिर्माण दूसरी और तीसरी योजना अवधि के अलावा अर्थव्यवस्था के अग्रणी क्षेत्र में कभी नहीं रहा है।

विकास का अर्थ

कोई भी प्रमुख देश आर्थिक वृद्धि में विनिर्माण की मद्द के बिना गरीबी को कम करने या विकास को बनाए रखने में कामयाब नहीं हो सका है। इसका कारण यह है कि उद्योग (और विनिर्माण) में उत्पादकता स्तर कृषि या सेवाओं की तुलना में बहुत अधिक है। विनिर्माण आर्थिक विकास का इंजन है क्योंकि यह पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं की पेशकश करता है, तकनीकी को अपनाता है और अगले एवं पिछले के बीच संपर्क को स्थापित करता है जो अर्थव्यवस्था में सकारात्मक प्रभाव देता है।

अमेरिका और यूरोप में, 2008 के संकट के बाद, नव-उदारवादी नीतियों के पूर्ववर्ती समर्थकों ने अपने औद्योगिक क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए रणनीतिक सरकारी प्रयासों को शुरू किया। सिद्धांततः मुक्त बाजारों और व्यापार के लिए अपने स्वयं के नुस्खे की अवहेलना करते हुए। यूरोपीय संघ ने मोटर वाहनों, परिवहन उपकरण उद्योगों, ऊर्जा आपूर्ति उद्योगों, रसायनों और कृषि-खाद्य उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट पहलों की पहचान की है।

व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या UNCTAD के अनुसार पिछले दशक के भीतर 100 से अधिक देशों ने औद्योगिक नीतियों को व्यक्त किया है। हालाँकि, भारत में अभी भी कोई विनिर्माण नीति नहीं है। हालांकि, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ाना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करना, जैसा कि मेक इन इंडिया अभियान का उद्देश्य है, महत्वपूर्ण जरूर हो सकते हैं, लेकिन एक औद्योगिक नीति का गठन नहीं कर सकते हैं।

यहाँ तक कि नवपारंपरिक अर्थशास्त्री (Neoclassical Economist) बाजार की विफलता के मामले में सरकारी हस्तक्षेप को स्वीकार करते हैं। मुख्यधारा के अर्थशास्त्री बाजार की विफलता के विशिष्ट उदाहरणों की ओर संकेत करते हैं, जिनके लिए सरकार द्वारा संचालित औद्योगिक नीति की आवश्यकता होती है, पूंजी बाजारों में कमियां, आमतौर पर सूचना विषमताओं के परिणामस्वरूप; पैमाने पर अर्थव्यवस्थाओं के शोषण को रोकने के लिए पर्याप्त निवेश की कमी; सीखने और प्रशिक्षण में फर्म-स्तर के निवेश के संबंध में अपूर्ण जानकारी; और तकनीकी रूप से अन्योन्याश्रित निवेशों के बीच सूचना और समन्वय की कमी। ये अच्छे कारण हैं जो यह बताते हैं कि भारत में एक अर्थव्यवस्था-व्यापक योजना तंत्र की आवश्यकता क्यों है। हालाँकि, भारत को 1991 के पूर्व के दिनों के 'कमांड और कंट्रोल' वाले दृष्टिकोण से स्पष्ट रूप से अलग हो जाना चाहिए।

एक नीति के प्रमुख कारण

तो अब भारत में औद्योगिक नीति की आवश्यकता क्यों है? पहला, जब पैमाने की अर्थव्यवस्था और पूंजी बाजार की खामियाँ मौजूद हों, तो पूरक निवेशों को समन्वित करने की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए, जैसा कि एक विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में परिकल्पित किया गया है। दूसरा, औद्योगिक नीतियों को औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए सब्सिडी जैसे बाहरी क्षेत्रों को संबोधित करने की आवश्यकता है (जिस पर हमने खराब प्रदर्शन किया है)।

वास्तव में, औद्योगिक नीति को मानव पूंजी में राज्य के निवेश, विशेष रूप से सामान्य अकादमिक के साथ-साथ व्यावसायिक

शिक्षा/प्रशिक्षण के साथ-साथ अधिकांश पूर्वी एशियाई देशों में औद्योगिक नीति के साथ सुदृढ़ किया गया था। हालांकि, मानव पूंजी की कमी भारत में ऐतिहासिक रूप से विदेशी निवेश (जो दक्षिण पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को आकर्षित करने में सफल रहा) को आकर्षित करने में एक बड़ी बाधा रहा है।

तीसरा, राज्य विदेशी कंपनियों या सरकारों के साथ अपनी बातचीत में घरेलू कंपनियों के आयोजक की भूमिका निभा सकते हैं - 1990 के दशक की बड़ी व्यावसायिक क्रांति (ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन के बीच मेगा-विलय और अधिग्रहण के साथ) के बाद 21 वीं सदी में विशेष रूप से प्रासंगिक भूमिका। वास्तव में, 1990 के दशक के बाद से चीन की औद्योगिक नीतियों का एक उद्देश्य ऐसी कंपनियों के विकास का समर्थन करना है (उदाहरण के लिए, लेनोवो कंप्यूटर, हायर घरेलू उपकरण और मोबाइल फोन बनाने वाली मेगा-फर्म)।

चौथा, औद्योगिक नीति की भूमिका न केवल समन्वय विफलताओं (यानी पूरक निवेश सुनिश्चित करना) को रोकना है, बल्कि पूंजी-दुर्लभ वातावरण में प्रतिस्पर्धात्मक निवेश से भी बचना है। अतिरिक्त क्षमता की वजह से मूल्य युद्ध (price Wars) होते हैं, कंपनियों के मुनाफे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है - या तो फर्मों का दिवालिया होता है या निवेश धीमा हो जाता है और भारत में ऐसा देखने को अक्सर मिल जाता है, जिसका एक उदहारण भारत का विमानन क्षेत्र है। इससे भी बदतर, भारत में दूरसंचार क्षेत्र में मूल्य युद्धों ने मुनाफे को धीमा कर दिया है (यहाँ तक कि अब नुकसान भी हो रहा है), जो ग्रामीण भारत के मोबाइल/इंटरनेट कवरेज में निवेश को बाधित करता है, जहाँ इसकी सबसे अधिक जरूरत है। पूर्वी एशियाई देशों ने औद्योगिक नीति की इस भूमिका को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया है।

पाँचवां, एक औद्योगिक नीति यह सुनिश्चित कर सकती है कि स्थापित औद्योगिक क्षमता यथासंभव न्यूनतम कुशल पैमाने के करीब हो। क्षमता के बहुत छोटे पैमाने का चयन करने का मतलब उत्पादन क्षमता में 30-50% की कमी हो सकती है। 1980 के दशक के अंत तक, 836 उत्पाद समूह केवल एसएसआई (जो अनौपचारिक उद्यमों को प्रोत्साहित करते हैं) द्वारा उत्पादित 'आरक्षित' श्रेणी में थे। आश्चर्यजनक रूप से, 2005 में, आर्थिक सुधार शुरू होने के 15 साल बाद भी इस श्रेणी में 500 उत्पाद थे। इसके बाद छोटी कंपनियों के उत्पादों के आरक्षण में 16 उत्पादों की कटौती की गई। तब तक, छोटे पैमाने और अनौपचारिकता भारतीय विनिर्माण में उलझ गई थी।

छठा, जब संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता होती है, तो औद्योगिक नीति उस प्रक्रिया को सुविधाजनक बना सकती है। तेजी से बदलते बाजार में, हारने वाली फर्में संरचनात्मक परिवर्तनों को रोक देंगी, जो सामाजिक रूप से लाभकारी हैं लेकिन अपनी संपत्ति को बेकार बना देंगी। पूर्व एशियाई सरकारों ने इस तरह की कंपनियों को संरचनात्मक परिवर्तन को कम करने से रोक दिया।

दुर्भाग्यवश, भारत, लैटिन अमेरिका और उप-सहारा अफ्रीका के कई प्रसिद्ध परिणामों के साथ रूढ़िवादी प्रतिमान के बढ़ते प्रभुत्व के बाद 1980 के दशक की शुरुआत से औद्योगिक नीति की संभावित भूमिका पूर्वी एशिया के बाहर के विकासशील देशों में लगातार कम हो रही है।

एशियाई कहानी

पूर्वी एशियाई चमत्कार बहुत कुछ निर्यात आधारित विनिर्माण पर आधारित था, जो कृषि द्वारा जारी अधिशेष श्रम को उपयोग में लाता है, इस प्रकार मजदूरी बढ़ती है और गरीबी तेजी से कम होती है। यह परिणाम जानबूझकर नियोजित रणनीति (पंचवर्षीय योजनाओं के साथ) से आया है। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में पूर्वी एशियाई देशों की बढ़ती भागीदारी ने निर्यात के लिए उपभोक्ता वस्तुओं को और अधिक प्रौद्योगिकी और कौशल-गहन विनिर्माण के लिए निर्मित किया, जो औद्योगिक नीति का एक स्वाभाविक आधार था।भारत द्वारा 'मेक फॉर इंडिया' पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के बावजूद विनिर्माण के बढ़ते निर्यात को एक औद्योगिक नीति के लिए एक और औचित्य की आवश्यकता होगी। 2014 से 2018 तक वस्तु निर्यात में डॉलर के संदर्भ में पूर्ण गिरावट आई है।

आईटी टेक रूट से सबक

यदि अभी भी सबूत की आवश्यकता है कि भारत में विनिर्माण विकास के लिए राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, तो भारत के आईटी उद्योग की सफलता की कहानी में राज्य की भूमिका को उजागर करना होगा। सरकार ने आईटी सॉफ्टवेयर पार्कों के लिए उच्च गति की इंटरनेट कनेक्टिविटी बनाने में निवेश किया, ताकि भारतीय आईटी उद्योग का अमेरिकी बाजार में एकीकरण हो सके। दूसरा, सरकार ने आईटी उद्योग को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के लिए शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति दी। तीसरा, आईटी उद्योग दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत कार्य करने में सक्षम था; इसलिए यह श्रम से संबंधित 45 कानूनों के अधीन नहीं है। अंत में, आईटी क्षेत्र को तकनीकी शिक्षा में पहले सार्वजनिक निवेश द्वारा बनाई गई कम लागत, उच्च मूल्य वाली मानव पूंजी का लाभ प्राप्त है। इनके बिना, आईटी सफलता की कहानी संभव नहीं है। यह आने वाली सरकार के लिए औद्योगिक नीति के संदर्भ में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत ने 23 स्थानों की जबरदस्त छलांग लगाते हुए 77वां स्थान हासिल किया है।
- विश्व बैंक ने 31 अक्टूबर, 2018 को वैश्विक कारोबार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) रिपोर्ट जारी की। भारत की यह रैंकिंग अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
- दस में से 8 मानकों में भारत की स्थिति सुधरी है।
- दरअसल, पिछले वर्ष 190 देशों की सूची में भारत को पहली बार शीर्ष 100 में जगह मिली थी।
- पिछले 2 वर्षों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की रैंकिंग में सुधार करने वाले टॉप 10 देशों में भारत भी शामिल है।
- दक्षिण एशियाई देशों में भारत की रैंक फर्स्ट है। इससे पहले साल 2014 में भारत 6वें स्थान पर था।

क्या है?

- ईज ऑफ डूईग बिजनेस से अर्थ है कि देश में कारोबार करने में कारोबारियों को कितनी आसानी होती है।
- कारोबार के नियामकों और उनके नियमों के अनुसार 10 मानकों पर कारोबार करने की शर्तों को देखा जाता है कि किसी देश में ये कितना आसान या मुश्किल है।
- डूईग बिजनेस रैंकिंग डिस्टेंस टू फ्रंटियर (डीटीएफ) के आधार पर तय की जाती है और यह स्कोर दिखाता है कि वैश्विक मानकों पर अर्थव्यवस्था कारोबार के मामले में कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है।
- वर्ष 2018 में भारत का डीटीएफ स्कोर पिछले साल के 60.76 से बढ़कर 67.23 पर आ गया है।

दुर्लभ उपलब्धि

- भारत द्वारा 'कारोबार में सुगमता' सूचकांक में लगाई गई 23 पायदानों की ऊंची छलांग निश्चित तौर पर महत्त्वपूर्ण है क्योंकि पिछले वर्ष इस सूचकांक में भारत ने अपनी रैंकिंग में 30 पायदानों की जबर्दस्त छलांग लगाई थी, जो भारत के आकार वाले किसी भी विशाल एवं विविधतापूर्ण देश के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि है।

मुख्य बिंदु

- कारोबार सुगमता रैंकिंग में न्यूजीलैंड शीर्ष पर है। उसके बाद क्रमशः सिंगापुर, डेनमार्क और हांगकांग का नंबर आता है।
- सूची में अमेरिका आठवें, चीन 46वें और पाकिस्तान 136वें स्थान पर है। विश्व बैंक ने इस मामले में सबसे अधिक सुधार करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत को दसवें स्थान पर रखा है।
- भारत ने दो वर्षों में अपनी रैंकिंग में 53 पायदानों की ऊंची छलांग लगाई है जो डूइंग बिजनेस आकलन में वर्ष 2011 के बाद किसी भी बड़े देश द्वारा दो वर्षों में की गयी सर्वाधिक बेहतरी को दर्शाता है।

कैसे तय होती है यह रैंकिंग?

- भारत ने वर्ष 2003 से अब तक 37 बड़े सुधार लागू किए हैं। इस रिपोर्ट में वर्ष 2017 में दिल्ली और मुंबई को शामिल किया गया था।
- रिपोर्ट में किसी कारोबार को शुरू करना, कंस्ट्रक्शन परमिट, क्रेडिट मिलना, छोटे निवेशकों की सुरक्षा, टैक्स देना, विदेशों में ट्रेड, कॉन्ट्रैक्ट लागू करना और दिवालिया शोधन प्रक्रिया को आधार बनाया जाता है।

Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अंकटाड (UNCTAD) 1964 में स्थापित एक अंतरसरकारी निकाय है।
2. 2017 में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का योगदान 18% था।
3. भारत की अंतिम औद्योगिक नीति 1990 में घोषित की गई थी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) 1 और 2
(c) 2 और 3
(d) 1, 2, और 3

1. Consider the following statements-

1. UNCTAD is an intergovernmental body established in 1964.
2. The proportion of manufacturing in gross domestic product was 18% in 2017.
3. The last Industrial Policy of India was declared in 1990.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) 1 and 2
(c) 2 and 3
(d) 1, 2 and 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्नः- नई औद्योगिक नीति का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है, ताकि संपूर्ण विश्व के समक्ष भारत को एक सशक्त विनिर्माण केन्द्र के रूप में स्थापित किया जा सके। टिप्पणी कीजिए। **(250 शब्द)**

Q. The main objective of the new industrial policy is to encourage the modern techologies like Internet of Things, Artificial Intelligence, Robotics so that India can be establised as a rigid manufacturing centre in the world. **(250 Words)**

नोट : 16 मई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d) होगा।

World Committed To Excellence